Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 1 | May 2023 - October 2023 | pp. 141-147

पाक-प्रायोजित आतंकवाद का भारत-पाक सम्बन्धों पर प्रभाव

डॉ. नीतू शर्मा

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान (विद्या सम्बल)
राजकीय महाविद्यालय, पीपाड़ सिटी, जोधपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों में कड़वाहट का एक बहुत बड़ा कारण भारत में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों का संचालन होना है। पंजाब, असम और जम्मू कश्मीर में ये आतंकवादी गतिविधियाँ स्पष्ट रूप से पाकिस्तान समर्थित नजर आती है। भारत में आतंकवाद पाकिस्तान में स्थित उन आतंकवादी संगठनों का कारनामा है जिन्हें पाकिस्तान की आई.एस.आई. से समर्थन-सहायता प्राप्त होती है। वहीं पूर्वोत्तर की आतंकी गतिविधियों एवं नक्सलवादी आन्दोलन के तार भी कहीं न कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. से जुड़े दिखाई देते है। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री बन गया है। वहाँ आतंकी शिविरों के पुख्ता सबूत है। सर्जिकल स्ट्राईक में भारत ने ऐसे ही लॉचिंग पेड को ध्वस्त किया था। इस शोध-पत्र के माध्यम से भारत व पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को प्रभावित करने वाली विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों को विश्लेषित करने का प्रयास किया जायेगा और उन आतंकवादी गतिविधियों और उसका दोनों देशों के बीच सम्बन्धों पर पड़े प्रभावों का विस्तार से विवेचन किया जायेगा। इसके लिए ऐतिहासिक एवं पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया है।

संकेताक्षर—*आतंकवाद, सर्जिकल स्ट्राईक, लॉचिंग पेड, आत्मघाती हमले, खुफिया एजेंसी*

प्रस्तावना

हिंसा, उपद्रव, हत्याएँ, विस्फोट, निर्दोष जान-माल की क्षति आदि का भय दिखा कर अपनी नाजायज माँगों को मनवाने हेतु दबाव डालना ही 'आतंकवाद' है। भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों में कड़वाहट का एक बहुत बड़ा कारण भारत में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों का संचालन होना है। आतंकवाद न सिर्फ पाकिस्तान से संचालित है अपितु अब तो इसका स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद ने अपने विभिन्न स्वरूपों में विश्व को प्रभावित किया है। इनमें स्वतन्त्रता प्राप्ति, धर्म, रक्षा, प्रजाति-संरक्षण तथा कई स्थानीय समस्याओं के आधार पर विकसित स्वरूप प्रमुख हैं। इन स्वरूपों को ही वस्तुतः आतंकवाद का प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है। इस्लामी आतंकवाद की समस्या से मध्य एशिया के देश सर्वाधिक ग्रस्त हैं। इस्लामी आतंकवाद का उद्देश्य धार्मिक उन्माद पैदा कर कथित मुस्लिम सिद्धान्तों का प्रसार करना है। इस्लामी आतंकवाद को हवा देने वाले देशों में सबसे प्रमुख नाम अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है। सऊदी अरब से निष्कासित अरबपति आतंकवादी 'ओसामा बिन लादेन' प्रायः सभी मुस्लिम आतंकवादी गुटों का मसीहा बना हुआ था।

भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् ही जम्मू-कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान, वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ चलाता रहा है। जम्मू-कश्मीर के कारगिल क्षेत्र को अवैध घुसपैठ से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर वहाँ सैन्य कार्यवाही की, जिससे मुस्लिम उग्रवादियों और पाकिस्तानी सैनिकों को वहाँ से भागना पड़ा। इस्लामी आतंकवाद से पीड़ित भारत लम्बे समय से इस आतंकवाद के खिलाफ विश्व स्तर पर आवाज उठाता रहा है। भारत ने नब्बे के दशक की शुरूआत में ही अमेरिका को भी मुस्लिम आतंकवाद के प्रति अपनी चिंता

से अवगत करा दिया था, लेकिन अमेरिका उस समय सब कुछ समझते हुए भी अनजान बना रहा। इसका कारण यह था कि उन दिनों और उससे भी पहले अमेरिका और सोवियत संघ तथा दोनों महाशक्तियों के बीच 'शीत युद्ध' की स्थिति बनी हुई थी तथा अमेरिका को बड़े पैमाने पर अपने हथियार बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का साम्यवादी प्रभाव था, जो अमेरिका को फूटी आँख नहीं सुहाता था। इसलिए उसने अभावग्रस्त पाकिस्तान को हथियारों और धन से मदद देना शुरू किया, ताकि वहाँ आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जा सके और प्रशिक्षित आतंकवादियों की मदद से अफगानिस्तान तथा भारत में अशांति फैलायी जा सके।

एक समझौते के तहत 1991-92 में अफगानिस्तान से सोवियत सेनायें वापस हो गईं लेकिन दुर्भाग्य से उसी दौरान सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके 15 राज्यों ने स्वयं को अलग-अलग देशों के रूप में स्वतन्त्र घोषित कर लिया। इनमें सबसे बड़ा देश रूस बना, जो सोवियत संघ का कुछ हद तक उत्तराधिकारी भी है।[1] लेकिन विघटन के साथ ही सोवियत संघ के ये टुकड़े भयानक मन्दी के शिकार हो गये और जिस सोवियत संघ को कभी अमेरिका अपना प्रतिद्वंद्वी समझता था, वही बदली परिस्थितियों में याचक की भूमिका में उसके सामने आ गया। उधर अफगानिस्तान, जो सोवियत फौजों की वापसी के बाद शक्तिहीन हो चुका था, वहाँ विभिन्न गुटों के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ गया। इस बीच पाकिस्तानी मदरसों में इस्लाम और आतंकवाद की शिक्षा पाये 'तालिबान' ने भी वहाँ हस्तक्षेप किया और शेष गुटों को शिकस्त देकर 'मुल्ला मुहम्मद उमर' के नेतृत्व में अफगानिस्तान मे अपनी कट्टर इस्लामी सत्ता स्थापित कर ली।

इसके बाद अमेरिका के लिए भी परेशानी शुरू हुई। इसी परेशानी की पराकाष्ठा तब दिखायी दी, जब अगस्त 1998 में तंजानिया और केन्या स्थित अमेरिकी दूतावासों पर किये गये बम विस्फोट में अनेक अमेरिकी नागरिक मारे गये। इस हमले में 'ओसामा बिन लादेन' का हाथ बताया गया। इस घटना के बाद अमेरिका की नींद खुली उसने लादेन को विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी घोषित कर उसके सिर पर 50 लाख डालर का इनाम घोषित कर दिया।

इस्लामी आतंकवाद की यह पराकाष्ठा 2001 में दिखाई दी जब जम्मू-कश्मीर की विधानसभा पर हमला किया गया। इसके बाद 11 सितम्बर को अमेरिका के विश्व व्यापार केन्द्र, 13 दिसम्बर को भारत की संसद पर आतंकी हमला, इससे पूर्व भारतीय विमान का अपहरण कर इन सभी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रति भारत के दृष्टिकोण की तरफ खुलकर ध्यान अमेरिका और सम्पूर्ण विश्व का गया।[2]

1990 से 2001 के मध्य भारत-पाक सम्बन्ध और आतंकवाद

सन् 1990 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ। भारत में विश्वनाथप्रताप सिंह के संसद में पराजित होने के बाद कांग्रेस (ई) के सहयोग से चन्द्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन वे भी सरकार को नहीं चला सके। तत्पश्चात् 1991 में भारत में आम चुनाव हुआ और जून 1991 में पी.वी. नरसिंहाराव भारत के प्रधानमन्त्री बने। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगस्त 1990में पाकिस्तान के राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान द्वारा बेनजीर भुट्टो को बर्खास्त करके नवाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया गया। भारतीय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहाराव ने पदभार ग्रहण करते ही कहा कि भारत दोनों देशों के मध्य व्याप्त मतभेदों को शिमला समझौते की भावना के अनुरूप शान्तिपूर्ण ढंग से हल करना चाहता है। 6 अक्टूबर 1991 में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में आयोजित राष्ट्रमण्डलीय देशों के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री राव और पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों की वार्ता हुई।

इसी प्रकार 8 नवम्बर 1991 को श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में एक बार फिर कश्मीर मुद्दे का पाक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया गया।[3] 11 नवम्बर 1991 का पाकिस्तान के विदेश राज्य मन्त्री मोहम्मद सिद्दिकी ने इस्लामाबाद में कहा कि—"पाकिस्तान कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। वह कश्मीर के आंतकवादियों को नैतिक तथा राजनैतिक समर्थन देता रहेगा।"[4] पाकिस्तान द्वारा इस तरह गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिये जाने से दोनों देशों के मध्य कड़वाहट आ गई। इसी वजह से मई 1992 में इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक के साथ पाकिस्तानी पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जिसके कारण विदेश सचिव स्तर की जून माह में आरम्भ होने वाली वार्ता को स्थगित करना पड़ा।[5] इसी वर्ष में आतंकवादी गतिविधियों

को बढ़ावा देने में पाकिस्तान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने भारत के आन्तरिक मामलों में अपना हस्तक्षेप जारी रखा।

राम मन्दिर-बाबरी मस्जिद विवाद और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन—6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के लिए मांग कर रहे कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। यह मस्जिद बाबर के सिपहसालार मीरबांकी ने एक मन्दिर को गिरा कर बनाई थी, ऐसी हिन्दुओं की मान्यता थी। इसके परिणामस्वरूप भारत सहित पूरे उपमहाद्वीप में साम्प्रदायिक विद्वेष भड़क उठा। अयोध्या की घटनाओं का लाभ उठाकर पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ, अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ धुआँधार प्रचार में जुटे किन्तु पाकिस्तान के ही अनेक क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाजें उठाई गई।

पाकिस्तान की शह पर मुम्बई में बम विस्फोट एवं आतंकवाद—12 मार्च 1993 को बम्बई महानगर में भयंकर शक्तिशाली विस्फोट हुए। कई स्थानों पर एक ही साथ विस्फोटों का होना एक अन्तर्राष्ट्रीय साजिश का ही परिणाम है।[6] इसका मुख्य उद्देश्य भारत की प्रगति और स्थिरता को आघात पहुँचाना है। प्रधानमंत्री राव की यह आशंका सही प्रतीत हुई कि षड्यन्त्रकारी उग्रवादी भारत की आर्थिक प्रगति को गहरा आघात पहुँचाना और विदेशी पूंजी निवेशकों को भारत में पूंजी निवेश के प्रति निरूत्साहित करना चाहते है। 18 मार्च 1993 को बम्बई पुलिस ने इस बात का पता लगा लिया कि बम्बई की घटनाएँ एक माह पूर्व दुबई में रची गई साजिश का परिणाम है। महानगर पुलिस आयुक्त अमर सिंह सामरा ने बताया कि सरकार की मुक्त व्यापार नीति को बाधा पहुँचाने के लिए मेमन बन्धुओं के टाइगर गिरोह ने फरवरी के मध्य में विस्फोट कराने की साजिश रची थी।[7] मेमन बन्धुओं ने ऐसा इसलिए किया कि मुक्त व्यापार नीति से उनका सर्राफा बाजार, हवाला तथा मादक पदार्थों का धन्धा प्रभावित हो रहा था। 24 मार्च को इस बात की पुष्टि हो गई कि मेमन परिवार के 6 सदस्य अब्दुल रज्जाक, सुलेमान मेमन, हनीफा, याकूब,, रहीम, युसुफ अब्दुल रज्जाक, 17 मार्च को ही विमान द्वारा दुबई से पाकिस्तान के कराची चले गए। भारत सरकार उस समय से मेमन बन्धुओं का वापस भारत भेजे जाने के लिए पाकिस्तान सरकार से सहयोग की मांग कर रही है।

पाकिस्तान सरकार द्वारा भी मेमन बन्धुओं को पाकिस्तान में शरण दिया जाना भारत-पाक सम्बन्धों में कटुता का एक और नया कारण है। विदेश मन्त्री दिनेश सिंह ने 3 अप्रैल को दक्षिण एशियाई विदेशी संवाद क्लब में स्पष्ट किया कि या तो पाकिस्तान मेमन बन्धुओं को लौटा दे अन्यथा उसे एक आतंकवादी राज्य के रूप में पेश किए जाने की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। बम्बई बम विस्फोट काण्ड के बाद यह तथ्य भी उजागर हुआ कि पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी इण्टर सर्विस इंटेलिजेन्स (आई.एस.आई) की नशीले पदार्थों के तस्करों के साथ भी गहरी सांठगांठ है और मेमन बन्धुओं को भी हर प्रकार का सहयोग एवं सहायता प्रदान करती रही है। 10 अप्रैल 1993 को पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ ने आदेश जारी किए कि बम्बई बम विस्फाटों के प्रमुख सन्देही मेमन बन्धुओं को यदि वे हकीकत में पाकिस्तान में ही हैं, गिरफ्तार करने के लिए तुरन्त टास्क फोर्स का गठन किया जाए।[8]

चरार-ए-शरीफ दरगाह पर आतंकवादी हमला और पाकिस्तान—कश्मीर में हिंसा और अलगाववादी आन्दोलनों तथा आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की साजिशों का पर्दाफाश हुआ। न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को पाकिस्तान का असली चेहरा देखने को मिला। भारत पाकिस्तान के मध्य चल रहे तनावपूर्ण सम्बन्धों में और अधिक कटुता आई। इसके पीछे-सूफी सन्त नुरूद्दीन नूरानी की पवित्र दरगाह में आतंकवादियों ने 10 मई 1995 की रात को 11 बजे विस्फोट कर दरगाह को आग लगा दी।[9] यह पवित्र स्थान कश्मीरियत की आधारशिला, सूफीवाद की धर्मनिरपेक्षता और सहनशीलता का स्मारक था। कश्मीर के मध्य के बड़गाम जिले और श्रीनगर से 45 कि.मी. दूर स्थित चरार-ए-शरीफ हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों की आस्था का केन्द्र है। रणनीतिक महत्त्व का स्थान होने के कारण चरार-ए-शरीफ दरगाह सीमा पार के घुसपैठ करने वालों के लिए शरणस्थली रही है। दिसम्बर 1991 तक आतंकवादी दण्ड से बचने के लिए चरार में आकर रहते थे और मार्च 1995 में जब सेना ने यह आशंका बताकर कि हजरतबल की पुनरावृत्ति हो सकती है, कस्बे को घेरना आरम्भ कर दिया, तो चरार में आतंकवादियों की संख्या 75

पहुँच गई थी। सेना की मोर्चाबन्दी के कारण इस क्षेत्र से मार्च 1995 से ही निवासियों का निकलना शुरू हो गया था और अप्रैल के अन्त तक 20,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में 1000 लोग रह गये थे। सेना के अधिकारियों के अनुसार 8 मई की शाम गुल ने सभी आतंकवादियों को दरगाह के अहाते में एकत्रित होने को कहा, जहाँ उन सभी ने नमाज अदा की। आतंकवादियों ने दरगाह से 200 मीटर दूर रिहायशी इलाके बाबा मुहल्ला के कुछ घरों में आग लगा दी। आतंकवादी इस भगदड़ में निकलना चाहते थे। अग्निशमन कार्य आरम्भ होने तक दो-तिहाई कस्बा जल चुका था। दरगाह सुरक्षित थी परन्तु 10 मई की रात दरगाह में आग की लपटें उठने लगीं। सेना ने कार्यवाही की और 20 आतंकवादी मारे गये।[10] पाकिस्तान के फैजलाबाद का निवासी और हरकत उल अंसार का स्वयंभू मुखिया अबू जिंदाल गिरफ्तार कर लिया गया जिसनें यह स्वीकार किया कि पाकिस्तान के हरकत उल अंसार ने मुझे कश्मीर घाटी में भेजा।

जम्मू-कश्मीर में इस दौरान विदेशी पर्यटकों का अपहरण और उसके बाद नार्वे के पर्यटक की हत्या से जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों द्वारा अपनाई जा रही नृशंस कार्यवाहियों का पता चला। इस अपहरण की जिम्मेदारी कथित अल-फरान संगठन ने ली ओर हरकत-उल-अंसार के उन सदस्यों की रिहाई की मांग की जो जेल में बन्द थे। इस संगठन का मुख्यालय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है।

भारत-शिमला समझौते की रूपरेखा के अनुसार पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत के जरिये सभी मतभेदों को सुलझाने की अपनी नीति के अनुरूप 1995 के सम्पूर्ण वर्ष के दौरान पाकिस्तान के साथ किन्हीं पूर्व शर्तों के बिना द्विपक्षीय बातचीत पुनः शुरू करने की अपनी इच्छा दोहराता रहा। सार्क शिखर सम्मेलन 2-4 मई 1995 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति फारूख लेधारी भारत यात्रा पर आए किन्तु पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सशर्त और नकारात्मक रही।

पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा भारतीय विमान का अपहरण व कंधार प्रकरण—24 दिसम्बर 1999 को काठमाण्डू से दिल्ली आने वाले इण्डियन एयरलाइन्स के एक यात्री विमान का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। इस विमान को दुबई ले जाया गया और वहाँ से अफगानिस्तान के कंधार में उतारा गया।[11] 25 दिसम्बर को अपहरणकर्त्ताओं ने अपनी मांग प्रस्तुत की जिसमें पाकिस्तानी नागरिक हरकत अल मुजाहिद्दीन के पूर्व नेता मौलाना मसूद अजहर की भारतीय जेल से रिहाई के लिए कहा। साथ ही दो अन्य आतंकवादियों— अहमद उमर सय्यद शेख और मुस्ताख अहमद जरगर की भी रिहाई की मांग की गई। अन्ततः भारत सरकार 154 यात्रियों के बदले इन आतंकवादियों को छोड़ने को मजबूर हो गई।[12]

इस अपहरणकाण्ड से यह तो स्पष्ट हो गया कि जिन आतंकवादियों को छुड़ाया गया वे सभी पाक समर्थित और कश्मीर में आतंक फैलाने का कार्य कर रहे थे। मुक्त होते ही वे फिर पाकिस्तान पहुँचे और आज भी वे आम सभाएँ कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा पर आतंकवादी हमला— आतंकवाद के विरूद्ध अमरीका की व्यूह रचना के जारी रहते और भारत के अपने कूटनीतिक प्रयासों को बनाये रखते एक और धमाका हुआ। चेतावनी दी आतंकवाद ने उसके मुकाबले में उतरने के उपक्रम में व्यस्त लोकतांत्रिक विश्व और भारत को कि वह झुकने के लिए तैयार नहीं है। 1 अक्टूबर 2001 को, श्रीनगर में स्थित जम्मू-कश्मीर विधानसभा परिसर के कड़े सुरक्षा कवच को भेदते हुए आतंकवादियों ने एक घातक हमला किया।[13]

विधानसभा भवन के मुख्य द्वारा पर एक कार में आत्मघाती बम विस्फोट किया गया जिसमें कम से कम 38 लोग मारे गए। जैशे मुहम्मद उग्रपंथी संगठन जिसने इस हमले का दावा किया उसका गठन उसी मसूद अजहर ने किया था, जो उन तीन लोगो में से एक था जिन्हें इण्डियन एयरलाइंस के एक विमान अपहरणकाण्ड में भारतीय जेलों से मुक्त कर दिया गया था।

जम्मू-कश्मीर में यही इस्लामी या जिहादी आतंकवाद थमने की बजाय और तूफान मचाये ही रहा। 18 अक्टूबर 2001 को उग्रपंथियों का एक गिरोह पुंछ से पीर पंजाल होता हुआ शोपियान गाँव में शरण लेने के लिए पहुँचा। भारतीय सुरक्षा बलों को ज्यों ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने कार्यवाही की। दुबजेन-हरिपुर में, जो पुलवामा जिले में है, वहाँ तलाशी के दौरान हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन अल बदर के चार चरमपंथी मारे गए और तीन सेनिक मारे गए जहाँ सेना ने 26 किलोग्राम आर.डी.एक्स. और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए।[14]

इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीस ने अक्टूबर में छपी 'द मिलिट्री बेलेन्स 2001-2002 (सैनिक, सन्तुलन) शीर्षक के साथ अपने नवीनतम प्रतिवेदन में कहा—"पाकिस्तानी सैनिक खुफिया संस्था आई.एस.आई. कश्मीर स्थिति मुस्लिम छापामार आन्दोलन लश्करे तॉयेबा को सक्रिय समर्थन कर रही है।"[15]

संसद भवन पर आतंकवादी हमला—13 दिसम्बर 2001 को भारतीय समयानुसार प्रातःकाल 11 बज कर 40 मिनट के आसपास एक एम्बेसेडर कार बाहरी सुरक्षा कवच को भेदकर संसद परिसर में घुस गई। यह कार जब गेट नम्बर 12 की और बढ़ी तो उसका सामना उपराष्ट्रपति के मोटर कार काफिले से हुआ। सुरक्षा स्टाफ के एक सदस्य जगदीश प्रसाद यादव को शंका हुई और वह कार के पीछे भागा। कार पीछे को मुड़ी ओर उपराष्ट्रपति की कार के साथ टकराई। सुरक्षाकर्मियों ने उसमें सवार लोगों को ललकारा तो पाँच आतंकवादी बाहर निकले और उन्होंने अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। वहाँ ड्यूटी पर पुलिस एवं सुरक्षाकर्मियों ने तुरन्त मोर्चे सम्भाल लिए और जवाबी फायरिंग की। गोलीबारी में संसद भवन के एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगी। वह गेट नम्बर 11 से अन्दर घुस गया और उसे बन्द कर दिया। तभी अलार्म चालू कर दिया गया और इमारत को अन्दर से बन्द कर दिया।[16]

भारतीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार "गोलीबारी में दिल्ली पुलिस के चार कर्मी, असिस्टेन्ट सब इंस्पेक्टर नानक बन्द और रामपाल, दो हैड कॉन्स्टेबल ओम प्रकाश और घनश्याम, घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। तीन अन्य जिनमें एक महिला कांस्टेबल श्रीमती कमलेश कुमारी, संसद भवन के एक सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव जो आतंकवादियों की कार के पीछे भागे थे और एक नागरिक कर्मचारी देशराज भी शहीद हो गए। घटनास्थल पर कई हथगोले पाए गए जिन्हें बाद में नाकाम बना दिया। बहुत बड़ी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद भी बरामद हुआ।"

अभियुक्तों से पूछताछ में यह रहस्योद्घाटन हुआ कि अफज़ल मुख्य समन्वयक था जिसे आतंकवादी संगठन जैशे मुहम्मद से सम्बद्ध एक पाकिस्तानी नागरिक गाज़ी बाबा ने यह काम सौंपा था। इससे पूर्व अफज़ल को पाकिस्तान के कब्जे के कश्मीर में मुज़फ्फराबाद में आई.एस.आई. द्वारा संचालित एक शिविर में प्रशिक्षण दिया गया था। शौकत हुसैन गुरु ने पाँचों पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए दिल्ली में छुपने के स्थानों की व्यवस्था की थी। उनमें से दो स्थान मुखर्जीनगर और एक उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर इलाके में थे।

भारत के गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवानी ने अपने वक्तव्य में कहा, "यह घटना एक बार फिर सिद्ध करती है कि भारत में आतंकवाद पाकिस्तान में स्थित उन आतंकवादी संगठनों का कारनामा है जिन्हें पाकिस्तान की आई.एस.आई. से समर्थन-सहायता प्राप्त होती है। इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई.सी. 814 का अपहरण, लाल किले में आतंकवादी घुसपैठ और श्रीनगर में विधानसभा भवन पर 1 अक्टूबर को किया गया हमला ये सब आई.एस.आई. द्वारा प्रोत्साहित उग्रपंथी संगठनों द्वारा किए गए हैं। लश्करे तॉएबा और जैशे मुहम्मद विशेष रूप से हमारे देश में आतंकवादी हिंसा के प्रयोजन में अग्रणी रहे हैं। भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में बुलाकर शाब्दिक विरोध प्रकट करते हुए यह मांग की गई कि इस्लामाबाद संसद भवन पर किए गए हमले के लिए जिम्मेदार दोनों आतंकवादी संगठनों के विरूद्ध कार्यवाही करे।"[17]

2002 से 2014 तक भारत-पाक सम्बन्ध

आतंकवाद के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दबाव विशेषतः अमरीका व ब्रिटेन के दबाव तथा भारत के कूटनीतिक हमले के आगे झुकते हुए पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने 12 जनवरी 2002 को यह घोषणा सार्वजनिक रूप से की कि पाकिस्तान में रह रहे किसी भी व्यक्ति को दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस सन्देश में मुशर्रफ ने भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शांति और वार्ता का पैगाम दिया।[18]

अपने तीखे तेवर दिखाते हुए मुशर्रफ ने भारतीय संसद पर हमले के लिए जिम्मेदार लश्कर एक तॉएबा व जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबन्ध लगाने के साथ-साथ देश में जातीय हिंसा के लिए जिम्मेदार तीन उग्रवादी इस्लामी संगठनों पर भी प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा की। इन संगठनों में शियाओं का तहरीक-ए-जफारिया, सुन्नियों का सिपाह-ए-सहावा तथा तहरीक-ए-निफज-ए-शरियत (मोहम्मदी) शामिल थे। मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तान की धरती से आतंकवादी कार्यवाही की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।[19]

भारत द्वारा वांछित 20 आतंकवादियों के मामले में टिप्पणी करते हुए मुशर्रफ ने कहा कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत के हवाले नहीं किया जाएगा। इनमें से किसी के विरूद्ध सबूत भारत द्वारा उपलब्ध करवाए जाने पर पाकिस्तानी नियमों के तहत ही उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल भारत ने 16 अक्टूबर, 2002 को उस समय की जब अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर से बड़ी संख्या में सैनिकों को हटाने की घोषणा उसने की, इसके तहत् अपने अतिरिक्त सैनिकों को हटाने की घोषणा भारत सरकार ने की थी जिन्हें 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन परिसर में पर हुए आतंकी हमले के बाद तैनात किया गया था, ऐसे सैनिकों की संख्या 6-7 लाख के बीच थी, इन्हें वापस बुलाने का निर्णय सुरक्षा पर मंत्रिमण्डलीय समिति (CSS) की 16 दिसम्बर की बैठक में लिया गया था, जम्मू-कश्मीर में नियन्त्रण रेखा पर तैनात सैन्य कर्मियों की पूर्ववत् बरकरार रहेगी। इस प्रकार सेना की तैनाती के मामले में 13 दिसम्बर, 2001 से पूर्व की स्थिति बहाल हो गई थी।

भारत-पाकिस्तान द्वारा नाभिकीय प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान—पूर्व वर्षों की भाँति 2003 में भी वर्ष प्रारम्भ पर भारत व पाकिस्तान ने अपने नाभिकीय प्रतिष्ठानों की सूची का औपचारिक आदान-प्रदान राजनयिक माध्यम से किया। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता एवं अतिरिक्त विदेश सचिव अजीज अहमद खान ने पाकिस्तानी नाभिकीय प्रतिष्ठानों की सूची वहाँ स्थित भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय में 1 जनवरी, 2003 को सौंपी। उसी दिन नई दिल्ली ने अपने ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची पाकिस्तानी उच्चायुक्त कार्यालय में सौंपी।[20]

भारत एवं पाकिस्तान द्वारा एक-दूसरे के कार्यवाहक उच्चायुक्तों का निष्कासन—भारत एवं पाकिस्तान के पास्परिक रिश्तों में कड़वाहट चरम पर फरवरी 2003 में उस समय पहुँच गई जब दोनों देशों ने एक-दूसरे के कार्यवाहक उच्चायुक्तों को निष्कासित कर दिया। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाने पर भारत ने पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त जलील अब्बास जिलानी व उच्चायोग के चार अन्य कर्मचारियों को देश छोड़ने का आदेश 8 फरवरी को दिया था। उसके कुछ घण्टों के भीतर की जवाबी कार्यवाही करते हुए इस्लामाबाद स्थित भारतीय कार्यकारी उच्चायुक्त सुधीर व्यास व उच्चायोग के चार अन्य कर्मचारियों को 48 घण्टे के भीतर देश छोड़ने का आदेश पाकिस्तान सरकार ने दे दिया। पाकिस्तान के इस फैसले को बदले की कार्यवाही बताते हुए भारत के सरकार ने कहा कि इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण हरकतें जारी रखे हुए है तथा वह अच्छे दोस्ताना सम्बन्ध नहीं रखना चाहता। उधर पाकिस्तान ने भारत के उपर्युक्त निर्णय को राजनयिक आतंकवाद करार दिया।

2014 से 2023 तक पाक प्रायोजित आतंकवाद एवं भारत पाक सम्बन्ध

2014 में भारत में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की सरकार के गठन के बाद भी भारत में विभिन्न पाक प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियां जारी रही। इनमें पठानकोट हमला, उरी हमला, और पुलवामा हमला प्रमुख है। भारत ने इन हमलो के पश्चात् अपना रूख कड़ा किया। जहां पठान कोट हमले के पश्चात् पाकिस्तान को उसके आतंकवादीयों की करतूतों के सबूत सौपें और उसे खुद जाँच करने के लिए पठान कोट आने दिया, वहीं उरी हमले के बाद सर्जीकल स्ट्राईक और पुलवामा में सी.आर.पी.एफ. के जवानों पर 14 फरवरी 2019 को किये गये आत्मघाती हमले के पश्चात् 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राईक करके पाकिस्तान को मजबूती के साथ जवाब दिया।" जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद यहा पर आतंकी गतिविधियों में कमी आई है। इस सन्दर्भ में प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है—

- 2015 से साल 2019 के बीच जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की 5063 घटनाएं हुई थी।
- 2019 से साल 2023 के बीच महज 434घटनाएं हुई हैं।
- पत्थरबाजी की घटनाओं में 91 फीसदी की गिरावट आई है।
- 2015 से साल 2019 के बीच जहां 597 आतंकियों की भर्ती हुई तो साल 2019 से साल 2023 के बीच यह संख्या 461 थी।"[21]

निष्कर्ष

निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों में कडवाहट का मुख्य कारण पाक प्रायोजित

आतंकवाद है। 2014 में भारत में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की सरकार के गठन के बाद भी भारत में विभिन्न पाक प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियाँ जारी रही। इनमें पठानकोट हमला, उरी हमला, और पुलवामा हमला प्रमुख है। भारत ने इन हमलों के पश्चात् अपना रूख कड़ा किया। जहां पठानकोट हमले के पश्चात् पाकिस्तान को उसके आतंकवादीयों की करतूतों के सबूत सौंपे और उसे खुद जाँच करने के लिए पठान कोट आने दिया, वहीं उरी हमले के बाद सर्जीकल स्ट्राईक और पुलवामा में सी.आर.पी.एफ. के जवानों पर 14 फरवरी 2019 को किये गये आत्मघाती हमले के पश्चात् 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राईक करके पाकिस्तान को मजबूती के साथ जवाब दिया। दोनों देशों के सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए पाक प्रायोजित आतंकवाद का समाप्त होना आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची

1. खण्डेला, मानचन्द, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2002, पृ.सं. 150
2. उपर्युक्त, पृ.सं. 156
3. रत्तू, कृष्ण कुमार, दक्षिण एशिया आतंक का साया और सार्क घोषणा, बुक एन्कलेव, जयपुर, 2005, पृ.सं. 183
4. उपर्युक्त
5. इण्डिया टुडे, 1 जून 1992 संस्करण, पृ.सं. 36
6. दैनिक भास्कर, 13 मार्च 1993, पृ.सं. 1
7. खण्डेला, मानचन्द, पूर्वोक्त, पृ.सं. 162
8. उप्रेती, डॉ. भूवन चन्द्र, भारत-पाकिस्तान विवादित मुद्दे (लेख), राजस्थान पत्रिका, जोधपुर, संस्करण, 16 जुलाई 2001, पृ.सं. 8
9. उपर्युक्त
10. समसामयिकी वार्षिकी, 1996, प्रतियागिता दर्पण, आगरा, पृ.सं. 143
11. दैनिक भास्कर, 26 दिसम्बर 1999, जोधपुर संस्करण
12. फ्रण्टलाइन (लंग्रेजी पत्रिका), 18 फरवरी 2000 के अंक में छपी रिपोर्ट
13. दीक्षित, जे.एन., भारत की विदेश नीति और आतंकवाद, पूर्वोक्त, पृ.सं. 229
14. दैनिक भास्कर, 19 अक्टूबर 2001, जोधपुर संस्करण
15. द मिलिट्री बेलेन्स 2001, इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, रिपोर्ट 2002, अक्टूबर, पृ.सं. 36
16. राजस्थान पत्रिका, 14 दिसम्बर 2001, जोधपुर संस्करण
17. दीक्षित जे.एन., पूर्वोक्त, पृ.सं. 242
18. दैनिक भास्कर, 13 जनवरी 2002, जोधपुर संस्करण
19. उपर्युक्त
20. गहलोत, एन.एस., सत्संगी अनु, इण्डो-पाक रिलेशन्स, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स प्रा. लि., न्यू देहली, 2004, पृ.सं. 184
21. हुसैन, सय्यैद दाबीर, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में आई कमी, राज एक्सप्रेस, 23 अगस्त 2023